



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2009/27 भाद्रपद, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 17 सितम्बर, 2009

संख्या: पर(एपी-बी)बी(1)-1/98.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या: पर(एपी-बी)बी(1)-1/98 तारीख 6-10-1998 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के गठन की बाबत अधिसूचना का और संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

1. पैरा-1 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड की अधिसूचना तारीख 6-10-1998 के विद्यमान पैरा-1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“बोर्ड, अध्यक्ष और चार से अनधिक सदस्यों से गठित होगा ।”

आदेश द्वारा,
आशा स्वरूप
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this department Notification No. Per(AP.B) B(1)-1/98 dated 17-09 2009 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT
(Apptt.II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 17th September, 2009

No. Per(AP.B)B(1)-1/98.—In exercise of the powers conferred by Article 162 read with proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased further to amend the notification regarding constitution of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board issued vide Notification No. Per(AP.B)B(1)-1/98 dated 06-10-1998, namely.—

1. Amendment of Para 1.—In Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board notification, dated 06-10-1998, for the existing para-1, the following shall be substituted, namely.—

“The Board shall consist of a Chairman and not more than four Members.”

By order
ASHA SWARUP,
Chief Secretary.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला 171009, दिनांक 14 सितम्बर, 2009

संख्या पी0सी0एच0—एच0ए0(3)42 / 2009—16323—27.—क्योंकि विभाग मे, जिला चम्बा के विकास खण्ड मैहला, की ग्राम सभा अठलूई, के मुख्यालय को कलहेई से बदलकर स्थान देहरोली में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा(2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चम्बा के विकास खण्ड मैहला की ग्राम सभा अठलूई के मुख्यालय को कलहेई से बदलकर देहरोली में स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सर्वजनिक आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र मे प्रकाशित करने एवं जिला चम्बा के उपायुक्त को उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं ;

यदि ग्राम सभा अठलूई के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त चम्बा को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आपति या सुझाव, जो कोई भी हो ग्रहण नहीं किये जाएंगे ;

राज्य सरकार, जिला चम्बा, विकास खण्ड मैहला, की ग्राम सभा अटलूई के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त चम्बा की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव।

‘श्रम विभाग’

अधिसूचनाएं

शिमला-171001, 14 जनवरी, 2009

संख्या 11-1/95(Lab) I.D/2008-Rampur.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Narain Dass S/O late Sh. Khimi Ram, Village Shagan, PO Chowai, Tehsil Ani, Distt. Kullu, H.P. V/S The Incharge, Patato Development Centre, Khunaha, Chowai, Tehsil Ani, Distt. Kullu, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु समझौता न हो सका। इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether termination of the services of Sh. Narain Dass S/O late Sh. Khimi Ram w.e.f. 17.11.2005 by the The Incharge, Patato Development Centre, Khunaha, Chowai, Tehsil Ani, Distt. Kullu, H.P. and retaining the junior worker is legal and justified? If not, what relief of service benefits including compensation and seniority the above workman is entitled to?”

शिमला-171001, 24 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Nathu Ram S/O late Sh. Shankar Dass, Village Khajuherati, PO Cholgah, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु समझौता न हो सका। इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Nathu Ram S/O Shri Shankar Dass by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 27 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Nek Ram S/O Shri Sita Ram, Village Tatohai, P.O. Sidhpur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Nek Ram S/O Shri Sita Ram by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 28 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Noor Deen S/O Shri Dhana, Village Bhadyar, P.O. Brang, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता

न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Noor Deen S/O Shri Dhana by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 28 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Om Chand S/O Sh. Sukh Ram, Village- Karnohal, PO Sajao Piplu, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Sh. Om Chand S/O Sh. Sukh Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08-7-2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?”

शिमला-171001, 15 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Parkash Chand S/O Shri Amar Singh, Village Paroun, PO Seoh, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु समझौता न हो सका। इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Parkash Chand S/O Shri Amar Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08-7-2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?”

शिमला-171001, 27 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Partap Singh S/O Shri Roop Singh, Village Baniurak, P.O. Ropadi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु समझौता न हो सका। इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Partap Singh S/O Shri Roop Singh by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 14 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Phula Devi W/O Shri Banku Ram, Village Khanour, P.O. Seoh, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Smt. Phula Devi W/O Shri Banku Ram by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, w.e.f. 08-7-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 27 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Phula Devi W/O Shri Ramji, Village Khajuriti, P.O. Cholgaharh, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Smt. Phula Devi W/O Shri Ramji by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 17 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Phulmu Devi W/O Shri Dhana, Village Hawani, P.O. Baroti, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Smt. Phulmu Devi W/O Shri Dhana by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified ? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 1 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Prem Singh S/O Sh. Sher Singh, Village Baharu, PO- Sandhote, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P.V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Sh. Prem Singh S/O Sh. Sher Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08-7-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 15 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Prithi Pal S/O Sh. Roop Lal, Village Daruman, PO Ghiyun, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Sh. Prithi Pal S/O Sh. Roop Lal, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08-7-2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?”

शिमला-171001, 28 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Promila Devi W/O Shri Sant, Village Sanour, P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Smt. Promila Devi W/O Shri Sant Ram by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 15 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Raj Dev S/O Shri Jai Singh, Village Retkal, P.O. Sajao Piplu, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Raj Dev S/O Shri Jai Singh by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-7-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 24 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Raj Kumar S/O Shri Sher Singh, Village Fihad, P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Raj Kumar S/O Shri Sher Singh by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 1 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Raj Kumar S/O Sh. Inder Singh, Village-Hawani, PO- Ropadi, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Sh. Raj Kumar S/O Sh. Inder Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 28 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Raju Ram S/O Shri Shiv Ram, Village Dharjole, P.O. Dev Bradla, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Raju Ram S/O Shri Shiv Ram by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 27 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rajinder Singh S/O Shri Achhar Singh, Village Sanaur, P.O. Sari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Rajinder Singh S/O Shri Achhar Singh by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. *w.e.f.* 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 14 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Una.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rakesh Kumar S/O Sh. Pritam Chand, Village Mojowala, Naya Nangal, Tehsil Anandpur Sahib, Distt. Ropar, Punjab V/S The Managing Director, M/S Punjab Laminates Pvt. Ltd., 9-10 Industrial Estate Mehatpur, Distt. Una, H.P. (174315). के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether termination of the services of Shri Rakesh Kumar S/O Sh. Pritam Chand by The Managing Director, M/S Punjab Laminates Pvt. Ltd., 9-10 Industrial Estate Mehatpur, Distt. Una, H.P. (174315) *w.e.f.* 13-8-2002 without complying the provisions of the Industrial Disputes act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits including continuity in service and compensation the aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001, 15 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rakesh Kumar S/O Shri Amar Singh, Village Siathhi, P.O. Longani, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Rakesh Kumar S/O Shri Amar Singh by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-7-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 28 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rakesh Kumar S/O Shri Mast Ram, Village Majehar, P.O. Cholgargh, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Rakesh Kumar S/O Shri Mast Ram by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 28 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Ram Lal S/O Sh. Sawaru Ram, Village-Thana, PO- Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P./S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Sh. Ram Lal S/O Sh. Sawaru Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08-7-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 28 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ram Nath S/O Shri Ghamanda Ram, Village Hawani, P.O. Ropadi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Ram Nath S/O Shri Ghamanda Ram by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 17 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ramesh Chand, Village Garadu, P.O. Sajao Piplu, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Ramesh Chand by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. *w.e.f.* 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

शिमला-171001, 28 जनवरी, 2009

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ramesh Chand S/O Shri Durga Dass, Village Dandoo, P.O. Bradla, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, District Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार समझौता अधिकारी ने उक्त विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु समझौता न हो सका । इस रिपोर्ट पर पूर्ण गौर करने के उपरान्त व उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether retrenchment of services of Shri Ramesh Chand S/O Shri Durga Dass by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. *w.e.f.* 08-07-2005 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above Employer?”

न्यायालय श्री देवा सिंह नेगी (हि० प्र० से०), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा (हि० प्र०)

श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी व डा० ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी व डा० ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका लड़का विकास कुमार जिसकी जन्म तिथि 7-9-2004 है पंचायत अभिलेख ग्रीमा में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त विकास कुमार का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख और में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इशतहार के जारी होने के एक माह के भीतर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवा सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री गोपाल दास चौधरी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भटियात चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री चैचल सिंह पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी सलोह, प्र० चुवाड़ी, तहसील भटियात, जिला चम्बा
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम चैचल सिंह है जोकि पंचायत के रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम एंचल सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसमें नाम दुरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें उक्त नाम की दुरुस्ती के प्रति कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-10-2009 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गोपाल दास चौधरी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भटियात चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री गोपाल दास चौधरी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भटियात चुवाड़ी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

श्री तेज राम उर्फ तेजो राम पुत्र श्री मोहना, निवासी चलामा, डा0 घटासनी, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय से गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम तेज राम उर्फ तेजो राम है परन्तु राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त घटासनी में गलती से तेजो राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसमे नाम दुरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें उक्त नाम की दुरुस्ती के प्रति कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2009 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गोपाल दास चौधरी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भटियात चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रोहित जमवाल, मैरिज ऑफिसर एवम् उपमण्डल दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश

1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सीता राम, गांव तन अमरोह, डा0 अमरोह, भोरंज, जिला हमीरपुर।
2. श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री तारु राम, गांव मतहेड़ी, डा0 नसाही, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 16 ऑफ स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत शादी पंजीकरण करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री विनोद कुमार व श्रीमती आशा देवी ने दिनांक 4-5-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार नवाही देवी माता मन्दिर में शादी कर ली है जिसे स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2009 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

रोहित जमवाल,
मैरिज ऑफिसर एवम् उपमण्डल दण्डाधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ढटवाल, उप-तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश

श्री जोगिन्दर चन्द पुत्र श्री वग्मू राम, निवासी टीका कोटला, तप्पा व सव-तहसील ढटवाल, जिला
हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि दर्ज किए जाने बारे।

प्रार्थी श्री जोगिन्दर चन्द पुत्र श्री वग्मू राम, निवासी टीका कोटला, तप्पा व सव-तहसील ढटवाल ने
अपना पुत्री अंकिता शर्मा की जन्म तिथि 1-4-2004 पंजीकरण करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। इस
बारे प्रार्थी ने शपथ-पत्र, पंचायत का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र भी पेश किया है।

अतः इस अदालती इशतहार द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को
जन्म तिथि 1-4-2004 पंजीकरण करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-10-2009 से पूर्व इस
अदालत में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है। बाद में आने पर कोई एतराज/उजर मान्य
स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देव राज शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ढटवाल,
उप-तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री गौरव चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री कुलदीप चन्द, निवासी चुड़था, डाकघर नरेगी, तहसील शाहपुर, जिला
कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री कुलदीप चन्द, निवासी चुड़था, डाकघर नरेगी, तहसील शाहपुर, जिला
कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया है कि उसकी सास श्रीमती पोस्तु देवी की मृत्यु
11 जनवरी 1987 को हुई है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है बाद मियाद गुजरने कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा श्रीमती पोस्तु देवी की मृत्यु तिथि 11 जनवरी 1987 के पंजीकरण के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गौरव चौधरी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री गौरव चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री हंस राज पुत्र श्री देस राज, निवासी कुरेला, डाकघर सदूँ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हंस राज पुत्र श्री देस राज, निवासी कुरेला, डाकघर सदूँ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया है कि उसकी लड़की अनू का जन्म दिनांक 19 मार्च 1988 को हुआ है मगर ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को जन्म तिथि पंजीकृत करने में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश कर सकता है।

आज दिनांक 8-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गौरव चौधरी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री गौरव चौधरी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम नकल पंचायत रजिस्टर व भूतपूर्व सैनिक प्रमाण—पत्र व स्कूल प्रमाण—पत्र में मलकीयत सिंह दुरुस्त है। परन्तु कागजात माल मिलखी राम दर्ज है। अतः मिलखी राम उर्फ मलकीयत सिंह दुरुस्त करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2009 को इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गौरव चौधरी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री गौरव चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

पेशी 27-10-2009.

श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री बाबू राम चौधरी, निवासी दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री बाबू राम चौधरी, निवासी दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके लड़के अनमोल चौधरी का जन्म दिनांक 12 अप्रैल, 2004 को हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश वह अपने लड़के का नाम जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2009 को असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबले समायत न होगा तथा प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गौरव चौधरी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनीश चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 110/NT/09

श्री Jamyang Nyima

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Jamyang Nyima पुत्र श्री Sonam Tashi, निवासी सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Kelsang Yeshe का जन्म दिनांक 20-3-1991 है। परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धपुर में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बच्चे Kelsang Yeshe का जन्म पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-9-2009 को अदालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-8-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनीश चौधरी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनीष चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 109/NT/09

श्री पूजा आनन्द

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री पूजा आनन्द पुत्र श्री तिलक राज, निवासी मोहली, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री आलोका आनन्द का जन्म दिनांक 16-10-2007 है। परन्तु ग्राम पंचायत सोकणी दा कोट में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बच्चे आलोका आनन्द का जन्म पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-10-2009 को अदालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-9-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनीश चौधरी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुमन कटोच

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सुमन कटोच पत्नी श्री सुमित कटोच, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र आदित्य वीर कटोच का जन्म दिनांक 23-9-2007 है। परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत सिद्धपुर में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बच्चे आदित्य वीर कटोच का जन्म पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 21-10-2009 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-9-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मखोली राम, गांव व डाकखाना झिकली भेट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मखोली राम, गांव व डाकखाना झिकली भेट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कमलेश का जन्म दिनांक

19-12-2006 को महाल झिकली भेठ में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2009 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 4-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

श्री देश राज पुत्र श्री मोहन लाल, गांव Chogan, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री देश राज पुत्र श्री मोहन लाल, गांव Chogan, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र संजय कुमार का जन्म दिनांक 19-7-1990 को महाल Chogan में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2009 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 4-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।

बी0 एस0 लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री निधु राम, गांव व डाकखना रनाटे, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री निधु राम, निवासी गांव व डाकखना रनाटे, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता विशनी देवी की मृत्यु दिनांक 15-11-1991 को महाल रनाटे में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2009 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 4-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

CHANGE OF NAME

I, Rekha Devi w/o Shri Sandeep Kumar, permanent resident of House No. 39/5, Nadaun, District Hamirpur, H.P. has changed my surname from Rekha Devi to Rekha Sandeep. I expressly authorise and request all persons at times, to designate and address me as Rekha Sandeep.

REKHA SANDEEP,
w/o Shri Sandeep Kumar,
Additional District Magistrate,
District Kangra at Dharamshala.

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री सोनम ग्यालसो पुत्र श्री पाम्पा, निवासी गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सोनम ग्यालसो पुत्र श्री पाम्पा, निवासी गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका पुत्र लोवजग दोरजे जो दिनांक

2-07-1975 को पैदा हुआ है, परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लोवजग दोरजे की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-10-2009 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री सोनम ग्यालसो पुत्र श्री पाम्पा, निवासी गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सोनम ग्यालसो पुत्र श्री पाम्पा, निवासी गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका पुत्र छेरिंग तेन्जीन जो दिनांक 1-03-1980 को पैदा हुआ है, परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को छेरिंग तेन्जीन की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-10-2009 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री सोनम ग्यालसो पुत्र श्री पाम्पा, निवासी गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सोनम ग्यालसो पुत्र श्री पाम्पा, निवासी गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री छेरिंग छोजुम जो दिनांक 1-03-1974 को पैदा हुई है, परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को छेरिंग छोजुम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-10-2009 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेन्द्र मोहन पुत्र श्री कुन्ज लाल, निवासी हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नरेन्द्र मोहन पुत्र श्री कुन्ज लाल, निवासी हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अंगीरस गुप्ता जो दिनांक 21-04-2008 को मृत्यु हुई है, परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सोयल के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अंगीरस गुप्ता की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-10-2009 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री गोन्पो नमज़ाल पुत्र श्री टशी, निवासी मॉडल टॉन मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री गोन्पो नमज़ाल पुत्र श्री टशी, निवासी मॉडल टॉन मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री छेरिंग डोलकर जो दिनांक 25-12-1983 को पैदा हुई है, परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को छेरिंग डोलकर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-10-2009 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री नरपत राम पुत्र श्री पुम्बा, निवासी वासा, डा0 गोहर, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरपत राम पुत्र श्री पुम्बा, निवासी वासा, डा0 गोहर, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी पुत्री का नाम छाया है जिसकी जन्म तिथि 26—9—2005 है। अज्ञानतावश वह अपनी लड़की का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत वासा के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि व नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह तिथि पेशी दिनांक 30—9—2009 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3—9—2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री दीवान चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी व डा0 चैलचौक, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दीवान चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी व डा0 चैलचौक, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी पुत्री का नाम प्रियंका है जिसकी जन्म तिथि 30—7—2006 है। अज्ञानतावश वह अपनी लड़की का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चैलचौक के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि व नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह तिथि पेशी दिनांक 30—9—2009 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
चच्चोट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री केवल राम, ग्राम जनोटी, ग्राम पंचायत देवरीघाट, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री केवल राम, ग्राम जनोटी, ग्राम पंचायत देवरीघाट, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपना नाम कृष्णा से दुरुस्ती करके मीना देवी रखने बारे आवेदन-पत्र गुजार रखा है। इसलिए ग्राम पंचायत देवरीघाट के रिकार्ड से कृष्णा से बदल कर मीना देवी रखने बारे आदेश दिए जाएं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती रोशनी पत्नी श्री रमेश, ग्राम दारो, ग्राम पंचायत सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रोशनी पत्नी श्री रमेश, ग्राम दारो, ग्राम पंचायत सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने गोदी पुत्री राखी गोद ले रखी है। जिसकी जन्म तिथि 20-10-2002 की है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सरोग में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती कमला पत्नी श्री सवलु, ग्राम क्यारी, ग्राम पंचायत सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला पत्नी श्री सवलु, ग्राम क्यारी, ग्राम पंचायत सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपनी पुत्री कमलेश जिसकी जन्म तिथि 15-7-2004 की है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सरोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती कमला पत्नी श्री मदन, ग्राम पुन्दर, ग्राम पंचायत कुठार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला पत्नी श्री मदन, ग्राम पुन्दर, ग्राम पंचायत कुठार, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने हल्फिया ब्यान दिया है कि कान्ता की शादी मेरी सहमती से मदन के साथ हुई है। जिसका पंजीकरण परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कुठार में नहीं हो सका है तथा पुत्री साक्षी जिसकी जन्म तिथि 25-8-2004 की है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कुठार में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री दौलत राम, ग्राम मातलु, ग्राम पंचायत बाघी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री दौलत राम, ग्राम मातलु, ग्राम पंचायत बाघी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपने पुत्र नमन जिसकी जन्म तिथि 12-9-2007 की है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बाघी में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री बेली राम पुत्र श्री बाला राम, ग्राम कदाई, ग्राम पंचायत बखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यर्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बेली राम पुत्र श्री बाला राम, ग्राम कदाई, ग्राम पंचायत बखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि० प्र०) ने अपनी पुत्री ईशान जिसकी जन्म तिथि 19-4-2002 की है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बखोल में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि० प्र०)

श्री सुरेन्द्र डोगरा पुत्र श्री रामानन्द, ग्राम गवाच, ग्राम पंचायत कलवोग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि० प्र०) ने अपने पुत्र तानीश डोगरा जिसकी जन्म तिथि 26-2-2008 की है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कलवोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यर्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेन्द्र डोगरा पुत्र श्री रामानन्द, ग्राम गवाच, ग्राम पंचायत कलवोग तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि० प्र०) ने अपने पुत्र तानीश डोगरा जिसकी जन्म तिथि 26-2-2008 की है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कलवोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री अनन्त राम पुत्र श्री मोही राम, ग्राम डरोल, ग्राम पंचायत नोहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अनन्त राम पुत्र श्री मोही राम, ग्राम डरोल, ग्राम पंचायत नोहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपनी माता स्व0 श्रीमती शुकरी जिसकी मृत्यु दिनांक 15-6-2009 को हो चुकी है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत नोहल से कटवाने बारे आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री जानिया राम पुत्र स्व0 श्री धनिया, ग्राम नोहल, ग्राम पंचायत नोहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

नाम की दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री जानिया राम पुत्र स्व0 श्री धनिया, ग्राम नोहल, ग्राम पंचायत नोहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपनी पत्नी श्रीमती गंगी का नाम ग्राम पंचायत नोहल में गलती से विमला दर्ज हुआ है इसलिए ग्राम पंचायत में विमला से तवदील करके गंगी रखने बारे आवेदन-पत्र गुजार रखा है। जिसकी जन्म तिथि 2-7-1969 है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बालक राम, ग्राम करयाली, ग्राम पंचायत कमाह, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बालक राम, ग्राम करयाली, ग्राम पंचायत कमाह, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपने पुत्र अंकुश का नाम ग्राम पंचायत कमाह में गलती से अशीश दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिए ग्राम पंचायत कमाह के परिवार रजिस्टर में अशीश की जगह अंकुश करने बारे आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हेम राज पुत्र श्री रतन लाल, निवासी कोलावाला भुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हेम राज पुत्र श्री रतन लाल, निवासी कोलावाला भुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री चंचल देवी जिसकी जन्म तिथि 5-6-2007 है का नाम ग्राम पंचायत कोलावाला भुड़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर चंचल देवी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री ललित कुमार पुत्र श्री पिताम्बर, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ललित कुमार पुत्र श्री पिताम्बर, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री वंशिका जिसकी जन्म तिथि 4-1-2007 है का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर वंशिका का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री सेवा राम, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री सेवा राम, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री महक कश्यप जिसकी जन्म तिथि 21-1-2009 है का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर महक कश्यप का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम पाल पुत्र श्री छेदी लाल, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री प्रेम पाल पुत्र श्री छेदी लाल, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी माता श्रीमती चन्दो देवी जिसकी मृत्यु तिथि 10-8-2007 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर चन्दो देवी का नाम एवं मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी गुन्नुघाट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राकेश कुमार पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी गुन्नुघाट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके दादा श्री सन्त राम जिसकी मृत्यु तिथि 30-12-1998 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर स्व० श्री सन्त राम का नाम एवं मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी० एस० गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी० एस० गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री खादिम उल इस्लाम पुत्र श्री खुदा बख्श, निवासी कन्टोनमैन्ट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री खादिम उल इस्लाम पुत्र श्री खुदा बख्श, निवासी कन्टोनमैन्ट एरिया, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री शबनम जिसकी जन्म तिथि 7-11-1995 है का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर शबनम का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी० एस० गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी० एस० गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री राज कुमार, निवासी नाहन बालमिकी बस्ती, तहसील नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री राज कुमार, निवासी नाहन बालमिकी बस्ती, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री कोमल जिसकी जन्म तिथि 18-10-1998 है का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर कोमल का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री ईशान मौ0 पुत्र श्री सुल्तान मौ0, निवासी बांका बाड़ा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ईशान मौ0 पुत्र श्री सुल्तान मौ0, निवासी बांका बाड़ा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं (ईशान मौ0) की जन्म तिथि 19-8-2004 है का नाम ग्राम पंचायत काला अम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर ईशान मौ0 का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती भन्ती देवी पुत्री श्री सरफु, निवासी काटल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती भन्ती देवी पुत्री श्री सरफु, निवासी काटल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं श्रीमती भन्ती की जन्म तिथि 13-6-1958 है का नाम ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर भन्ती देवी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द, निवासी कच्चा टैन्क नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राजेश कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द, निवासी कच्चा टैन्क 266/9, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र रितेश सैनी जिसकी जन्म तिथि 20-3-2003 है का नाम नगर पालिका कच्चा टैन्क 266/9 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रितेश सैनी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सीता राम पुत्र श्री धनी राम, निवासी काटल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सीता राम पुत्र श्री धनी राम, निवासी काटल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सपना जिसकी जन्म तिथि 10-5-2003 है का नाम ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सपना का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी ओलीवाला गाड़डा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी ओलीवाला गाड़डा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र साहिल कुमार जिसकी जन्म तिथि 20-11-2005 है का नाम ग्राम पंचायत नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर साहिल कुमार का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री लायक राम, निवासी मंडलांहा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री लायक राम, निवासी मंडलांहा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री रीता देवी जिसकी जन्म तिथि 14-1-2003 है का नाम ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रीता देवी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती चम्पा देवी पुत्री श्री शौकिन चन्द, निवासी चिड़ावाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती चम्पा देवी पुत्री श्री शौकिन चन्द, निवासी चिड़ावाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री पायल जिसकी जन्म तिथि 27-8-2004 है का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर पायल का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी० एस० गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी० एस० गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द, निवासी भालोंवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त श्री नरेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द, निवासी भालोंवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी दादी स्व० श्रीमती खानों देवी जिसकी मृत्यु तिथि 1-12-2007 को हो चुकी है, का नाम ग्राम पंचायत बनकला के रिकार्ड में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर स्व० श्रीमती खानों देवी का नाम एवं मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी० एस० गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी० एस० गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री शमशेर पुत्र श्री कश्मीरी खान, निवासी मोगी नन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शमशेर पुत्र श्री कश्मीरी खान, निवासी मोगी नन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सोनिया जिसकी जन्म तिथि 13-8-2007 है का नाम ग्राम पंचायत काला आम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2009 को सुबह दस बजे इस

अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सोनिया का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी० एस० गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना
(हि० प्र०)

श्रीमती बिमला देवी

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता ।

श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व० श्री अशोक कुमार पुरी, निवासी पास शिव मन्दिर मेन बाजार ऊना, तहसील ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र मोनू की मृत्यु गांव ऊना में दिनांक 9-8-1993 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2009 को सुबह दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-9-2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बरिन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)।

न्यायालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

विषय.—तस्दीक करने इन्तकाल क्रमांक 835 वरास्त मिन जानिब श्री नसीब सिंह पुत्र श्री सूरम सिंह, जाति राजपूत, गांव वासी उप—मुहाल भद्रकाली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम नसीब सिंह पुत्र श्री सूरम सिंह, जाति राजपूत, गांव भद्रकाली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

श्री गुरचरन सिंह पुत्र श्री किशन सिंह द्वारा आवेदन पेश हुआ कि मेरे चाचा श्री नसीब सिंह लगभग अरसा 25-30 वर्ष से घर से लापता है और आज दिन तक न कोई शादी-गमी पर किसी रिश्तेदार के घर आए और न ही कोई चिट्ठी या तार आई है। वह अरसा 25-30 वर्ष से लापता है। नसीब सिंह की वरास्त का इन्तकाल जोकि मेरे सगे चाचा जी हैं इन्तकाल नम्बर 835 दिनांक 17-8-2009 मकफूल उलखबरी नसीब सिंह पुत्र श्री सूरम सिंह, जाति राजपूत वाक्या उप—मुहाल भद्रकाली, तहसील अम्ब, जिला ऊना दर्ज रजिस्टर

होकर जेरे फैसला है। अतः उपरोक्त श्री नसीब सिंह ने दी गई कोई हितबद्ध व्यक्ति को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस इन्तकाल के तस्दीक होने में किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इशतहार के छाया होने के एक माह भीतर किसी भी कार्य दिवस में मेरे समक्ष हाजिर अदालत होकर एतराज पत्र प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार इन्तकाल का फैसला कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9-9-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

—————
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 7th September, 2009

No. GAD-C-F(1)-1/2008.—In continuation to this department notification of even No. dated 11-10-2005, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to publish the records and other activities of the General Administration Department as required under the provisions of sub section (1) (b) of Section 4 of the Right to Information Act, 2005 as under.—

PARTICULARS OF ORGANISATION, FUNCTIONS AND DUTIES :

(i) **ORGANISATION:** The General Administration Department is the nerve centre of the State administration. The Chief Minister is the Minister in-charge of General Administration Department. The General Administration Department functions under the supervision and guidance of the Chief Secretary and the Administrative Secretary. The work in the General Administration Department is organized in 5 sections viz. GAD-A, B, C, D, & E under the supervision of Branch Officers in the rank of Special/Additional/Joint/Deputy/Under Secretary (as the case may be).

(ii) **FUNCTIONS & DUTIES :**

Under the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, the following functions have been assigned to the General Administration Department.

(a) **General, Political & Miscellaneous**

1. Annual Administration Report—Instructions regarding.
2. Channel of correspondence between the Government of India, State Governments and abroad.
3. Death of High Dignitaries—Action to be taken on.
4. Discretionary grants—Matters relating to.
5. Move of Offices.
6. National Anthem.
7. National Integration.
8. National Security Rules.
9. Praman and Prashansa Patras.

10. Portraits of National Leaders.
11. Classification and re-classification of offices.
12. Re-organization of District Administration.
13. Security arrangements in offices.
14. Central and State Citizen Councils.
15. Accommodation including accommodation in the Secretariat, office and Residential accommodation for Deputy Commissioners and other Offices and all pooled residential accommodations.
16. Estate Office and allotment of Government accommodation.
17. Governor's Secretariat.
18. Governor's Address to Vidhan Sabha.
19. Matters relating to and arising out of Statehood.
20. Matters relating to boundary disputes.
21. Problems arising out of the Re-organization of Punjab in 1966 Including integration and allocation of services and division of assets and liabilities.
22. Development of Inter-State Border Areas – Matters relating to.
23. All matters relating to International Border including development of International Border Districts.
24. Indo-Tibetan Trade.
25. Northern Zonal Council Business.
26. Governor's Conference Business.
27. Administrative Officers Conference.
28. Merger of enclaves with Himachal Pradesh.
29. Demands from various organizations including political parties.
30. Secretariat staff and departmental cars.
31. Parliament Questions, Assembly Questions (Affecting more than one department).
32. Matters relating to Political Sufferers.
33. Post-war Services Reconstruction Fund.
34. Rulers, their properties and privy purses.
35. Fortnightly Reports to the Government of India.
36. Postal, Telegraphs, Telephones and Wireless facilities in Himachal Pradesh.
37. Representation from the Public of Himachal Pradesh.
38. Matters affecting more than one Department.
39. Administration of Himachal Pradesh Benevolent Fund.
40. Declaration of Gazetted and Local Holidays.
41. Independence Day, Republic Day, Himachal Day, Martyr's Day, U.N.O. Day and other Religious days—Celebration of.
42. Census.
43. Miscellaneous work.
44. Circuit houses and reservation of accommodation in such circuit houses and rest houses as from time to time by the Government.
45. Re-organization of Districts and Tehsils etc.
46. Rationalization of Committees at State/ District level—Instructions thereof.
47. District Relief Fund, Chief Minister's Relief Fund and other funds Collection of and other allied matters.
48. Honours and distinctions

(b) CONFIDENTIAL AND CABINET

1. Secret matters.
2. Meetings of the Cabinet and its Sub-Committees.
3. Allocation Rules and Rules of Business.

4. Ministers, Chief Parliamentary Secretary, Deputy Ministers, Parliamentary Secretary—All question relating to.

(c) HOSPITALITY AND PROTOCOL

1. Hospitality.
2. Protocol Matters.
3. State Guest.
4. Establishment budget and accounts matters.

(iii) ORGANIZATIONAL STRUCTURE:

In order to execute the above functions , the work in the General Administration Department is organized in the following sections:

GAD-A
GAD-B
GAD-C
GAD-D
GAD-E

The allocation of work among these sections is provided as under:

GAD-A Section :

1. Establishment of Drivers and workshop staff.
2. Declaration of State Guests and framing of State Guest Rules.
3. VVIPs visits.
4. Purchase of Vehicles for the use of Hon'ble Chief Minister/Ministers/Secretaries etc.
5. Arrangement of Helicopter.
6. Declaration of all kinds of holidays.
7. National/Distinctive flags and use of red light.
8. DCs/SPs/Governor's/Chief Minister's conference and Northern Zonal Council Meeting/Inter State Council Meeting.
9. All State level functions (State Hood Day, Republic Day, Himachal Day, Sadbhavna Divas, Anti Terrorism Day, Observance of Silence, working in Hindi).
10. Handling of cash.
11. Preparation of all kinds of bills of Drivers of GAD.
12. Passing of petrol and repair bills of vehicles.
13. Arrangement of lunch/dinner.
14. Passing of Canteen/Cabinet Meetings bill.

GAD-B :

1. Reorganization of administrative areas of Districts/ Divisions/ Sub Divisions/ Tehsils/ Sub Tehsils and creation/ upgradation of Tehsils and Sub Tehsils.
2. Boundary disputes.
3. Pension and other related matters of Ex-Rulers
4. Co-ordination with regard to Census work.
5. High Official Railway Reservation.
6. Correspondence relating to postal facilities in Himachal Pradesh.
7. Correspondence relating to Establishment and other matters of Governor Secretariat.

8. Correspondence relating to matters of Resident Commissioner's office, New Delhi.
9. Chief Minister Relief Fund.
10. Work relating to Honours and distinctions with regard to conferment of the following:

State Awards :

- (a) Himachal Gaurav Puraskar.
- (b) Prerna Srot Samman Puraskar and Correspondence relating to following awards of Government of India:—
- (c) Series of Padma Awards
- (d) Jeevan Raksha Padak series of awards.
- (e) Ashok Chakra series of Gallantry awards.

This Section makes liaison with Postal Department/Tele communications department for opening of new Sub-Post Offices and Public Call Offices on the demands of public.

GAD-C :

1. Meetings of the Cabinet.
2. Constitution of Cabinet Sub-Committee(s)
3. Implementation of Cabinet decisions.
4. Appointment of Ministers and Foreign tours by Ministers.
5. Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh.
6. Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules.
7. Acts and Rules concerning to Ministers/Speaker and Deputy Speaker, Chief Parliamentary Secretary/Parliamentary Secretary and MLAs.
8. Summoning and prorogation of Himachal Pradesh Vidhan Sabha Sessions.
9. Governor's Address during the first day of the first session of the calendar year.
10. Implementation of Election Manifesto.
11. National Integration/Quami Ekta Week.
12. Annual Administrative Report of General Administration Department.
13. To take permission from Hon'ble Speaker, Lok Sabha/Chairman, Rajya Sabha and Speaker, H.P. Vidhan Sabha for nomination of MPs/MLAs in various committees/Boards.
14. Visits of various Committees of Parliament/State Legislatures.
15. Establishment and other matters of H.P. Vidhan Sabha.
16. Ratification of Bills.
17. Chief Whips Conference.

GAD-D :

1. Allotment/Change/retention of General Pool accommodation.
2. Framing of House Allotment Rules and amendment thereof.
3. Reservation of suits in Himachal Bhawan/Sadan, New Delhi/Chandigarh/PWD Rest House Shimla and other related matters.
4. Matters relating to Establishment and Budget of Directorate of Estates.
5. Accommodation for Government offices in Shimla and Issuance of NOC.
6. Repair, addition/alteration etc. in General Pool residential accommodation.
7. Construction of new residential units of General Pool.
8. Allotment of servant quarters/garages.

GAD-E :

The General Administration Department "E" Section deals with the cases relating to the welfare activities of the Freedom Fighters of the State and their dependents. The Government has formulated a scheme namely, "Himachal Pradesh Swatantrta Sainani Samman Yojana-1985" under which the persons who had undergone the imprisonment for a cumulative period of not less than two months and/or were exterred or remained underground for a cumulative period of not less than two months for participation in the National Movements for Freedom before independence and/or in the movements for merger of the erstwhile princely states within the Indian Union after 15th August, 1947 till the date of accession of the State with Indian Union, are eligible for Samman Rashi, which is transferable to their legally wedded wives after their death. This Rashi is also transferable to their unmarried daughters in case of death of Freedom Fighters and their spouses. Facilities being provided to the freedom fighters are as under:—

- (i) The Samman Rashi is being paid @ Rs.4000/-P.M. to living Freedom Fighters & Rs.3000/- P.M. to their widows & unmarried daughters.
- (ii) Compensation of confiscated property of Freedom Fighters is provided to them on the recommendations of the Himachal Pradesh Freedom Fighters Welfare Board in shape of grant-in-aid.
- (iii) Rs.10,000/- is being provided as Grant-in-aid on the marriage of daughters/grand daughters of Freedom Fighters.
- (iv) Rs.5000/- is being provided Grant-in-aid on the death of Freedom Fighters.
- (v) Medical reimbursement facility is being provided through Chief Medical Officers of concerned districts.
- (vi) 2% reservation is being provided to the wards of freedom fighters in the jobs in Govt./semi Government departments of the State.
- (vii) One-one seat is being provided in Technical and Medical Institutions.
- (viii) Free traveling facility has been provided to the freedom fighters and their spouses for which passes/Identity Cards are issued.

All other grievances pertaining to Freedom Fighters and their dependents are taken up with concerned departments for implementation.

POWERS AND DUTIES OF ITS OFFICERS AND EMPLOYEES:

The Organization of the Department indicates the hierarchy of various officers in the department. The powers and duties of the officers of the General Administration Department are given at Annexure-1 & II.

2. Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability.

The department vide office order No.GAD-(CC)1(A)30/2008, dated 5-5-2009 has issued standing orders with regard to the cases disposed off at various level of officers in the General Administration. The detail is given at Annexure-II.

3. Norms set by it for the discharge of its functions:

The matters are dealt with as per provisions of various Government Acts, Rules & Regulations adopted from time to time and as indicated at Annexure-II

4. Rules, Regulations, Instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions

GAD-A :

- (i) Rules regulating the use and maintenance of the Government vehicles & conditions of service of Drivers in H.P.
- (ii) Livery Rules of Drivers & Workshop Staff.
- (iii) Himachal Pradesh State Guest Rules-1990(amended upto November, 2008.
- (iv) All other Civil Services Rules applicable to the employees of H.P. Govt.
- (v) Declaration of Public Holidays.

GAD-B :

- (i) Scheme/Guidelines for conferment of State Awards i.e. Himachal Puraskar and Prerna Srot Puraskar.

GAD-C :

- (i) The Himachal Pradesh Legislative Assembly(Allowances and Pension of Members(Act,1971.
- (ii) The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members(Removal of Disqualification) Act, 1971.
- (iii) The Himachal Pradesh State Legislative Officers, Ministers and Members(Medical Facilities) Act, 1971.
- (iv) The Himachal Pradesh State Legislature Proceedings(Protection of Publication) Act, 1977.
- (v) The Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's salaries Act, 1971.
- (vi) The Salaries and Allowances of Ministers(Himachal Pradesh) Act, 2000.
- (vii) The Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries(Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006.
- (viii) Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, 1971
- (ix) Business of the Government of Himachal Pradesh(Allocation) Rules, 1971.
- (x) The Himachal Pradesh Ministers Traveling Allowances Rules,2000.
- (xi) The Himachal Pradesh Ministers Advance For Motor Car and House Building Rules, 2000.
- (xii) The Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Traveling Allowances Rules, 1971.
- (xiii) The Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Advance for Motor Car and House Building Rules, 2001.

GAD-D :

- (i) H.P. Allotment of Government Residences(General Pool) Rules, 1994 and instructions issued there under.

GAD-E :

- (i) Charitable Endowment Act.
- (ii) H.P. Financial Rules.
- (iii) H.P. Swatantrta Sainiani Samman Yojana-1985.

5. A Statement of the categories of documents that are held by it or under its control.

GAD-A :

- (i) Agreement with M/S Simm Samm Airways to provide helicopter services to the State Government on wet lease.
- (ii) Agreement with M/S Naresh Tours & Travel for providing vehicles on lease to the Government departments.
- (iii) H.P.State Guest Rules.
- (iv) Maintenance of Government vehicles.

GAD-B :

- (i) Scheme/Guidelines for conferment of State Awards i.e. Himachal Gaurav Puraskar and Prerna Srot Puraskar.
- (ii) Record pertaining to C.M. Relief Fund.

GAD-C :

- (i) Annual Administrative Report of General Administration Department.
- (ii) Manual of Acts and Rules in respect of Ministers, Himachal Pradesh.
- (iii) Manual of Acts and Rules concerning the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker.
- (iv) Manual of Acts concerning members of Himachal Pradesh Legislative Assembly.

GAD-D :

- (i) Proceedings of the House Allotment Committee meeting.

GAD-E :

- (i) Himachal Pradesh Swatantrta Sainani Samman Yojna, 1985.
- (ii) Charitable Endowment Act.
- (iii) Proceedings of the meetings of Board and its sub-Committee.
- (iv) Record of freedom fighters.
- (v) State expenditure and Budget books pertaining above mentioned Scheme.
- (vi) Instructions pertaining to facilities being provided by other departments.

6. Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof. The scope of work in the General Administration Department does not involve any consultation with the public.

7. A Statement of the Boards, Councils, Committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards, Councils, Committees and other bodies are open to the public ,or the minutes of such meetings are accessible for public.

GAD-E :

- (i) H.P. Freedom Fighters Welfare Board.

(ii) Sub-Committee constituted under above Board.

8. A Directory of its officers and employees.

The directory of its officers and employees is given at Annexure-III

9. The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations.

A statement showing name of posts with classification and scale of pay is given at Annexure-IV

10. The Budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made.

There is no allocation under plan scheme.

11. The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes.

There is no subsidy programmes to be executed by this department.

12. The particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by its.

The Freedom Fighters so declared under “Himachal Pradesh Swatantrta Sainani Samman Yojna-1985”, wives of deceased freedom fighters and unmarried daughters of deceased freedom fighter and his spouse are the recipients of the Samman Rashi. The nearest kith an kin of the deceased freedom fighters are the recipients of grant-in-aid being paid for the funeral rights of deceased freedom fighters.

13. Details in respect of the information, available to or held by its, reduced in an electronic form.

14. The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.

Information relating to General Administration Department can be obtained from the designated Public Information Officer or on GAD website Himachal.gov.in/gad

15. The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.

Sl. No.	Designation	Telephone No.	Designated as
1.	Dr.Ajai Bhandari, Secretary (GAD) H.P. Secretariat, Shimla-2	2621892 (O) 2880722 (O)	State Appellate Authority
2.	Sh. J.R. Katwal, Special Secretary (GAD), H.P. Secretariat, Shimla-2.	2621007 (O) 2880710 (O)	State Public Information Officer

3.	Smt. Sumati Negi, Deputy Secretary (GAD), H.P. Secretariat Shimla-2.	2621110 (O)	—do—
4.	Sh. Harish Chander Negi, Section Officer (GAD-A), H.P. Secretariat, Shimla-2.	2880423	State Assistant Public Information Officer
5.	Smt. Savitri Joshi, Section Officer (GAD-B), H.P. Secretariat, Shimla-2.	2880424	State Assistant Public Information Officer
6.	Sh. Ramesh Verma, Section Officer (GAD-C), H.P. Secretariat, Shimla-2.	2880425	State Assistant Public Information Officer
7.	Sh. M.C. Kaundal, Section Officer (GAD-D), H.P. Secretariat, Shimla-2.	2880426	State Assistant Public Information Officer
8.	Sh. Rajinder Thakur, Section Officer (GAD-E), H.P. Secretariat, Shimla-2.	2880428	State Assistant Public Information Officer

17. Such other information as may be prescribed.

By Order,
Sd/-
Chief Secretary.

ANNEXURE-1

1. SECRETARY:

Secretary is the Administrative head of Department and is responsible for the proper transaction of Business allotted to the General Department.

2. SPECIAL SECRETARY/DEPUTY SECRETARY :

The Special Secretary/Deputy Secretary(as the case is the branch in-charge of the sections of General Administration Department and has generally to perform the following duties and functions:

- To go through (and initial with date) the dak received by him and mark the papers to the concerned section and also to give directions for its disposal whenever possible at the dak stage to enable speedy processing;
- To submit important communication to the superior officer at the dak stage for perusal and directions in case the same has not been seen by the officer;
- To dispose off receipts of secret/confidential or urgent nature after getting such receipts diarised in the concerned section for further reference;

- (iv) To deal with the receipts retained by him and to scrutinize cases received from the section and either finally dispose off the same at his level if powers stand vested in him under the statutory or standing orders or submit the cases to the higher authorities in complete form;
- (v) To devise from time to time measures necessary for expeditious disposal of business/work in a section; prepare the Annual Action Plan and to monitor and review the progress at regular intervals;
- (vi) To keep a watch over timely submission/receipt of returns/statements and to send the same to quarter concerned duly checked /scrutinized and ensure that all relevant statistical data /information relating to establishment, budget, expenditure, schemes, plans etc. relating to his section/ department and his particular assignment is always kept up-to-date. Also to ensure that all relevant Acts, Rules, Manuals, instructions, Guard file, precedent registers of the Department are kept updated.
- (vii) To maintain liaison with other departments with regard to various activities, schemes, programmes of the department and attend meetings to represent the department as and when directed by the superior authorities and to present the view point of the department as per directions of superiors. After attending the meetings the Branch officer or Middle level officer is required to submit a resume of the deliberations of the meetings.
- (viii) To monitor and inspect the ongoing schemes and suggest ways and means for improvements, if any; prepare, analyse and suggest new schemes, new innovations, improvements for the department.
- (ix) To allocate subjects to different sections under his charge; allocate work of a section amongst various dealing hands in consultation with the Section Officer.
- (x) To train and guide the staff under him and to point out their shortcomings and deficiencies if any, for remedial action.
- (xi) To keep himself acquainted with the morale, conduct and discipline of the staff posted in sections under him; ensure punctuality in attendance by the staff posted in the sections under his charge; make surprise visits to the sections under his charge to check attendance; to look to the difficulties of the staff; see observance of other instructions by the staff; and carry out periodical inspections of the sections as per provisions of office manual or directions of the authorities and to send inspection reports to the next higher authority as directed.
- (xii) To see that the Section Officers/Superintendents or Senior Assistants working under him hand over/take-over the charge in the manner prescribed in the office manual. The Branch officer can be assigned any other duty commensurate with his status and exigencies of public service.

3. SECTION OFFICERS :

The General Administration Department consists of five sections viz. GADA, B,C,D & E.

The Section officer is normally incharge of one section and has generally to perform the following duties and functions:—

-
- (i) To go through the dak as received by him and take the following steps:—
- (a) Mark the misssent receipts to the concerned sections;
 - (b) Submit the important communications for perusal of the higher authorities through Branch Officer, at dak stage, in case any such communication has not been seen by the said authorities;
 - (c) Retain receipts of secret/confidential or urgent nature which he may like to deal himself in which case the said receipts will be got diarised from the diarist by the Section Officer for further reference;
 - (d) Mark the remaining receipts to the concerned dealing hands with dated initials indicating the urgency and also giving directions, if any, for disposal and to hand over the same to the diarist of the section for diarizing and handing over to the concerned dealing hands;
 - (e) Keep a note in the diary about receipts for watching proper and timely disposal.
- (ii) To himself deal on relevant files, secret, confidential, urgent or complex receipts retained by him and also to scrutinize cases received from the dealing hands and further to dispose off the cases at his own level if so empowered under the standing orders or to submit the same to the Branch Officer with his own remarks or suggestion, if any.
- (iii) To see that the concerned dealing hands collect, compile and keep updated data/information relating to the establishment, budget, expenditure, schemes, plans etc. relevant to his section of posting;
- (iv) To see that the concerned dealing hands monitor, analyse and maintain data as to the achievement of targets of various on-going schemes both in terms of budget provision/expenditure and actual progress and also to suggest ways and means for improvements in the ongoing schemes; and assist the Branch Officer in preparation of new schemes/programmes, new innovations etc.
- (v) To ensure that returns /statements are submitted in time and the returns/statements to be received in the section are received in time;
- (vi) To see that all dealing hands and the diarist maintain all required registers and keep the same updated. He should also check these registers at regular intervals;
- (vii) To see that all routine duties including maintenance and updating of various registers are carried out promptly and thoroughly;
- (viii) To keep a careful watch on any holdup in the movement of dak and files between the section and higher officers; ensure timely submission of fixed date cases, other important cases and papers required by officers and to keep a watch on progress of action; devise from time to time measures necessary for expeditious disposal of work in the section; to make arrangement for disposal of work of officials of the section on leave, training etc.
- (ix) To prepare papers and compile data for meetings and ensure timely submission.
- (x) To be well acquainted with the office procedure and Acts, Rules, Manuals and instructions of a general nature relating to Finance, Personnel and General Administration Department and specifically applicable in the Departments/Section

where posted; see that all Manuals, Acts, Rules, instructions Guard files and Precedent Registers of the section are kept upto date by inserting correction-slips or getting new editions printed;

- (xi) To maintain liaison between the staff and the Branch Officer in various matters; train and guide the staff posted in the section and to point out their shortcomings and deficiencies, if any, for remedial action; keep himself well acquainted with the morale, conduct and discipline of the staff and also to ensure that the staff comply with Government instructions issued from time to time.
- (xii) To allocate evenly, work of the section to the staff posted in the section with the approval of the Branch Officer and to maintain updated distribution list of work amongst the dealing hands in the section;
- (xiii) To ensure punctuality in attendance in the section and to advise the staff on matters of conduct and discipline. For ensuring availability of staff posted under him on holidays or early or late hours, he should maintain local addresses with phone Nos. of the entire staff with him.
- (xiv) To see that the section is kept neat and tidy and that the files, papers etc. are arranged in an orderly manner; and the recorded files are sent to the record room.
- (xv) To ensure that the dealing hands maintain their Assistant's Diaries regularly and note the particulars of initial submission of cases and also record final disposal of receipts at appropriate stage of final disposal of the cases. He is also required to see that the interim processing of receipts leading to collection/compilation of data/information is not marked as final disposal in the Assistant's Diaries. Weekly checking of the Assistant's Diaries is also one of his important functions.
- (xvi) On transfer from one Department/Section to another, to hand over the charge and prepare list of important/complicated matters requiring immediate attention of the successor in accordance with the procedure prescribed in the office manual and to see that the officials transferred to or out of the section hand over/take over the charge in the manner prescribed in the manner prescribed in para 10.4 of the Hand book for Assistants and para 15.2.4 of Chapter XV of the Office Manual.
- (xvii) If it comes to the notice of the officer next below the authority who has passed the orders that such authority was not competent to take a decision, it will be his responsibility to bring it to the notice of such authority through the Branch Officer in writing before complying with those orders.

The above duties are of illustrative nature and the Section Officer(s) can be assigned any other duty commensurate with his status and exigencies of public service.

4. SUPERINTENDENTS :

Superintendents Grade-II working in the Secretariat supervise work of some of the dealing hands posted in a section and submit through the Section Officers, but while posted in an independent Cell, they may supervise the working of the entire cell and submit cases direct to the Branch Officer. Accordingly such Superintendents Grade-II of the Secretariat have virtually to perform all the duties and functions of Section Officers given in para above excepting that the Superintendent Grade-II when posted in a Section has not to perform duties as indicated in sr.nos.

(i),(Xii),(Xiii) and (Xvii) above, when the Section Officer is there and has to submit the cases through the Section Officer and he can neither finally dispose off any case at his level nor issue any communication under his signatures.

5. ASSISTANTS :

The term “Assistants” includes “Senior Assistants”, Senior Assistants(Accounts)” and “Junior Assistants” who deal with receipts and submit cases to the Section Officers or Superintendents. The Assistants are required to compile data, statistics or information and deal matters so as to present complete cases with all relevant data, and information with past precedents and viable/feasible solutions to facilitate the authorities to arrive at a definite decision. The Assistants are thus basic to the administrative machinery. Depending upon urgency, need and public interest, the Assistants can be asked to undertake any job/assignment, but generally, the main duties, functions and responsibilities of the Assistants involve handling of the work relating to:—

- (1) Receipt, diary dispatch, typing record maintenance.
- (2) Various duties in reception and varied assignments in offices of Ministers and senior officers.
- (3) Opening and maintenance of files, referencing, dealing cases including noting and drafting, recording of files, maintenance and updating of various types of data, statistics and information and maintenance of various registers.
- (4) Acquisition, maintenance and up-keep of stores, stocks, stationery articles, accounts and registers;
- (5) Preparation of all types of bills such as pay, traveling allowance, medical reimbursement, contingencies, contractors, suppliers and advances etc. etc. and handling of cash, maintenance of cash books and connected accounts/bills registers etc.;
- (6) Personnel/service/establishment matters, including recruitment and promotion rules, conditions of service, posting, transfers, maintenance of service books, index cards, service records, preparation of leave accounts, pension papers, disciplinary matters, personal files etc. etc.
- (7) Budget preparation including appropriation, re-appropriation, supplementary demands for grants, additional grants, contingency fund, all matters relating to Public accounts Committee, Estimates Committee, audit paras, economy in expenditure etc. etc.;
- (8) Assisting in planning and monitoring of developmental social and welfare schemes;
- (9) Regulatory matters such as issue of licences, permits, various types of certificates etc.;

6. CLERKS:

Clerks posted in the GAD sections have to perform duties and functions as assigned to them by the Section Officer/ Superintendent. General duties of clerks are as under:

- (i) To receive the dak from the Central Registry, other sources, give acknowledgement for the same and submit the entire dak to the Section Officer/ Superintendent for marking;
- (ii) To diarise all dak in the Refnic.;
- (iii) to see that communication from V.I.P.s, Assembly /Parliamentary Questions are entered in separate register.
- (iv) To distribute all dak after diarizing to the dealing hands as per marking by the Section Officer/ Superintendent against proper receipts of the dealing hands.
- (v) To procure stationery articles for the Section and to distribute the same.

- (vi) To do type work of the section, neatly, cleanly and accurately.
- (vii) To maintain casual leave account of the entire staff posted in the section.
- (viii) To open files.
- (ix) Properly maintain record and files as required in the Section of posting and to maintain all registers, prepare returns.

7. Supervisor(Staff Car) :

He is overall in-charge of GAD workshop as well as keep control on drivers/workshop staff of GAD and responsible to check the repair works of vehicles of GAD in the workshop.

8. Drivers:

These posts are mandatory under the one vehicle-one driver norms to ply the Government vehicles provided to the Ministers/Chief Secretary/ Principal Secretaries/ Secretaries/ State-guests/ VIP and other dignitaries.

9. Mechanic:

The duty of mechanic is to attend the repair work of defected vehicles received at the workshop on every day.

10. Blacksmith:

The blacksmith attend the work of hard iron parts of the vehicles which had gone out of order while plying during the course of long journey. They bring them in order by minor denting and welding to make the vehicle roadworthy.

11. Fitter :

The work of fitter is to remove old defected parts of the vehicles pointed out by the mechanic and to fit new spare- part.

12. HELPER:

The helper is required to assist all the above mentioned functionaries at sr.no. 6 to 10. He is also required to assist them in making handy the spare parts from the store of the workshop for speedy disposal of repair work.

क-अनुभाग

अनुबन्ध-क

मुख्य मन्त्री स्तर पर :

1. सचिवालय स्टाफ व विभागीय वाहनों के नियम बनाना ।
2. नयाचार से सम्बन्धित नीति निर्धारण ।
3. राजपत्रित तथा स्थानीय अपवकाशों की घोषणा ।

4. स्वतन्त्रता दिवस/गणतन्त्रता दिवस तथा अन्य राज्य उत्सव, शहीद दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस तथा अन्य धार्मिक दिवस समारोह मनाना/राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के स्थान का चयन ।
5. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्/अन्त-राज्य परिषद्/अन्य अन्तराज्य मामले तथा इसके सम्बन्धित अन्य मामले ।
6. प्रथम द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की आसामियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम ।
7. वास्तविक नई योजनाओं (आर0एन0एस0) से सम्बन्धित सभी पद ।
8. कार्य संचालन नियमावली के नियम 14,15,16,55 व दिए गए सभी मामले ।
9. विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तथा प्रस्तावों का अनुमोदन ।
10. कटौती प्रस्तावों का स्थगन ।
11. मन्त्रियों द्वारा विधान सभा में दिये गए आश्वासनों पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित रिपोर्ट ।
12. लोक सभा तथा राज्य सभा प्रश्नों से सम्बन्धित आवश्यक मामले, जिसमें सिद्धान्त या नीति शामिल हो ।
13. विधान सभा कार्य से सम्बन्धित सभी आवश्यक मामले जिसमें विधान सभा समिति भी सम्मिलित हो ।
14. चालकों की गोपनीय रिपोर्ट में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि तथा चालकों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही की अपील का निपटारा ।
15. कोई भी अन्य मामला जिसे माननीय मुख्य मन्त्री के ध्यान में लाना आवश्यक हों ।

ख-अनुभाग

मुख्य मन्त्री स्तर पर :-

1. **कार्य संचालन नियम**
कार्य संचालन नियम 14,15,16,55 में उल्लिखित मामले ।
2. **विधान सभा/लोक सभा कार्य**
 1. विधान सभा प्रश्नों, प्रस्तावों के उत्तर का अनुमोदन ।
 2. सिद्धान्तों तथा नीति से सम्बद्ध लोक सभा/राज्य सभा प्रश्न (केवल महत्वपूर्ण मामलों में) ।
 3. स्थगन और कटौती प्रस्ताव ।
 4. आश्वासनों, वायदों तथा बचनबद्धताओं के उत्तर ।
 5. विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट ।
3. **विधि सम्बन्धी मामले**
 1. विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियम बनाना ।
 2. विधेयक/अधिनियम, नियम, विनियम, नियमावली, संहिता कार्यपालक अनुदेश (मूल्यांकन, निर्धारण और व्याख्या इत्यादि) ।
4. **संगठन**
 1. कार्यालयों तथा संस्थाओं का गठन करना ।
 2. राज्य/जिलों की जिला स्तरीय शिकायत निवारण समितियों का गठन/निरस्त करने बारे ।
 3. अन्तर राज्य सीमा क्षेत्र सीमा का विकास। नीति विषयक सभी मामले। सीमा विवाद: नीति सम्बन्धी सभी विषय ।
 4. भाड़ा तथा गारंटी की स्वीकृति हेतु अनुमोदित डाक, तार एवं वेतार सुविधायें (सार्वजनिक दूरभाष कार्यालयों और बेतार केन्द्रों के सम्बन्ध में) तथा डाकघरों के सम्बन्ध में एन.आर.सी ।

5. पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न समस्याएँ, जिनमें सेवाओं के एकीकरण आबंटन। परिसम्पतियों तथा दायित्वों का आबंटन शामिल है।
6. शासक, उनकी सम्पति तथा राजभत्ता, शासकों की मान्यता तथा सम्पति अधिकार सहित उनके अधिकार को प्रभावित करने वाले विषय।
7. जनगणना : नीति सम्बन्धी सभी विषय।

5. नीति तथा कार्यक्रम

1. नए कार्यक्रमों का प्रतिपादन करना/मण्डल/जिला/तहसील/उपतहसील का व्यवस्थापन करना।
2. वर्तमान नीति में परिवर्तन।
3. पूर्व अनुमोदित योजनाओं मूलभूत प्रभार।

6. स्थापना

1. भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाना तथा सेवा शर्तों और नियमों में ढील देना।
2. कर्मचारियों द्वारा दिये गये स्मरण पत्र जिन्हें नियमों के अन्तर्गत मन्त्री के आदेश की अपेक्षा हो।

7. वित्तीय मामलों में बजटा खाता

1. 1,00,000/- रु० से अधिक व्यय वाले मामले।
2. 1,00,000/- रु० से अधिक कीमत की अप्रयोज्य वस्तुओं, हानियों के बट्टे खाते में डालना।
3. आय व्ययक अनुमान।
4. नई योजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृतियाँ।
5. अधीनस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन प्रतिरूप का मूल्यांकन।
6. सभी असैनिक राष्ट्रीय पुरस्कार एवं उनकी केन्द्र सरकार को सिफारिश।
7. मुख्य मंत्री राहत कोष।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक अथवा नीति के ऐसे मामले जिन्हें मुख्य सचिव आवश्यक समझें अथवा मुख्य मन्त्री उन्हें देखना चाहें, मुख्य मन्त्री महोदय को प्रस्तुत किये जाएंगे।

सी-अनुभाग

मुख्य मन्त्री स्तर पर :

1. मन्त्रीमण्डल की बैठक को निश्चित करने तथा उसके कार्यवृत्त को अनुमोदित करना।
2. राज्यपाल अभिभाषण को अनुमोदित करना तथा अभिभाषण को राज्यपाल महोदय की अन्तिम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (निरर्हताएं) अयोग्यता निवारण नियम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा।
4. विधान सभा सत्र को बुलाने तथा उसके सत्रावसान के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त करना।
5. हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य संचालन नियम तथा आबंटन नियमों में संशोधन करना।
6. मन्त्रियों/राज्य मन्त्रियों/उप मन्त्रियों/विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव को दी जाने वाली सुख सुविधा से पत्राचार।
7. राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में बुलाना।
8. हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य संचालन नियम के 26 व 27 के अन्तर्गत स्थाई आदेश जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति।
9. मन्त्रीमण्डल से सम्बन्धित गोपनीय विषय
10. विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तथा प्रस्तावों का अनुमोदन।

11. सभी नीति से सम्बन्धित मामलों पर मन्त्रियों द्वारा सदन में दिए गए आवश्वासनों से सम्बन्धित ।
12. बोर्डों/निगमों/समितियों में विधायकों को गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने सम्बन्धी मामले ।
13. मन्त्रियों द्वारा विदेशी यात्रा की स्वीकृति बारे ।
14. सामान्य प्रशासन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की स्वीकृति प्रदान करना ।
15. राज्य स्तरीय कौमी एकता सप्ताह मनाने से सम्बन्धित पत्राचार ।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक अथवा नीति के ऐसे अन्य मामले जिन्हें मुख्य सचिव आवश्यक समझे अथवा मुख्य मन्त्री उन्हें देखना चाहे, मुख्य मन्त्री महोदय को प्रस्तुत किये जाएंगे ।

डी-अनुभाग

मुख्य मन्त्री स्तर पर :

1. विधान सभा प्रश्न और विधान सभा कमेटियों से सम्बन्धित मामले ।
2. लोक सभा प्रश्न ।
3. नीति निर्धारण सम्बन्धी मामले ।
4. कार्यालयों को बदलने सम्बन्धी मामले ।
5. सम्पदा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश वर्ग-I व II श्रेणी अधिकारियों के मुख्य दण्ड निर्धारण सम्बन्धी मामले ।
6. प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय सम्बन्धी अनुमोदन जोकि हिमाचल प्रदेश वित्तिय नियम के अन्तर्गत आते हैं ।
7. वार्षिक योजना, पंच वर्षीय योजना रियली न्यू स्कीम जो सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित है ।
8. सम्पदा निदेशालय हिमाचल प्रदेश के पदों के सृजन व अन्नयन ।
9. मन्त्रियों के आवासों का आबंटन/बदलने/रखने सम्बन्धी मामले ।
10. आवास आबंटन नियमों में आवास आबंटन/बदलने/रखने सम्बन्धी संशोधन/रियायत देने सम्बन्धी मामले ।
11. मन्त्रियों के आवासों को निर्धारित अवधि से अधिक रखने/किराये निर्धारण करने सम्बन्धी मामले ।
12. सम्पदा निदेशालय हिमाचल प्रदेश में वर्ग-I व II के पदों को भरने सम्बन्धी मामले ।
13. हिमाचल भवन/सदन नई दिल्ली/हिमाचल भवन चण्डीगढ़ की दरों के निर्धारण सम्बन्धी मामले ।

ई-अनुभाग

मुख्य मन्त्री स्तर पर :

1. मुख्य मन्त्री महोदय हिमाचल स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण परिषद् के अध्यक्ष हैं । अध्यक्ष के नाते मुख्य मन्त्री महोदय स्वतन्त्रता सेनानियों के सभी कल्याण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करते हैं और जो भी योजनाएं, नीति, नियम उनके कल्याण कार्य हेतु बनाई जाती है या कोई भी नई सुविधा प्रदान करनी हो उसका निर्णय मुख्य मन्त्री महोदय करते हैं ।

क-अनुभाग

1. मुख्य सचिव स्तर पर :

1. बजट स्तर पर नव-व्यय अनुसूची में नई स्कीमें सम्मिलित करना ।
2. विभाग के कार्य पर वार्षिक रिपोर्ट ।
3. वित्त विभाग की सहमति से अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करना ।

4. चालकों/कार्यशाला स्टाफ की गोपनीय रिपोर्ट में की गई विपरीत प्रविष्टियों के विरुद्ध अपील।
5. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद व अन्य अन्तर्राज्य मामले में चर्चा करना तथा अन्तर्राज्य परिषद से सम्बन्धित मामले।
6. अन्य विविध प्रशासनिक महत्व या नीति के मामले जिसे मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री को दिखाना चाहें या अपने स्तर पर ही निपटारा चाहें।

2. प्रधान सचिव/सचिव के स्तर पर :

1. गुप्त प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध चालकों/कार्यशाला स्टाफ के प्रतिवेदन।
2. चालकों/कार्यशाला स्टाफ के प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर स्थानान्तरण।
3. वार्षिक बजट अनुमान (तकनीकी नई स्कीमें)।
4. अनुमान समिति/लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के अनुच्छेदों के उत्तर।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के चालकों व कार्यशाला स्टाफ की पदोन्नति/नियुक्ति/स्थाईकरण।
6. रिट/निर्णय के विरुद्ध अपील तथा न्यायालय में सरकारी खर्च पर सरकारी मामलों के बचाव की स्वीकृति।
7. 10,000/-रु० से ऊपर के प्रासंगिक खर्च की स्वीकृति।
8. सभी वित्तीय व अन्य विषय जिसके लिए विभागाध्यक्षों को विशेष अधिकार प्रत्यायोजित किए गये हैं।
9. चालकों व कार्यशाला स्टाफ पर वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम, 1965 के अन्तर्गत मेजर दण्ड अधिरोपित करना।
10. वित्तीय विभाग की सहमति से अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करना।
11. अराजपत्रित कर्मचारियों (चालकों/कार्यशाला स्टाफ) के विरुद्ध सिविल/अपराधिक मामलों का संस्थापन या वापिस लेना और कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध लगाई गई क्षति का राजस्व से भुगतान।
12. राज्य समारोहों के दौरान दिए गये भोजों में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की स्वीकृति।
13. लेखा अनुच्छेद-आपत्तियां तथा लेखा नियंत्रक की रिपोर्ट।
14. विविध शताब्दी मनाने के विषय में नीति/निर्णय।

3. विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/अवर सचिव के स्तर पर :

1. दक्षता रोध पार करने की अनुमति।
2. अस्थाई पदों का निरन्तरीकरण।
3. चालकों को पदस्थीकरण व स्थानान्तरण व लगाना।
4. अनुमोदित आदेशों के अनुसार स्थानान्तरण/पदस्थीकरण/नियुक्ति आदेश जारी करना।
5. चालकों तथा कार्यशाला स्टाफ से सम्बन्धित आचार संहिता के अन्तर्गत दी जाने वाली सभी अनुमतियां।
6. चालकों तथा कार्यशाला स्टाफ की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियों को सत्यापित करना।
7. चालकों तथा कार्यशाला स्टाफ को अर्जित अवकाश की स्वीकृति।
8. चालकों तथा कार्यशाला स्टाफ पर वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील नियम, 1965 के अन्तर्गत लघु दण्ड अधिरोपित करना।
9. चालकों तथा कार्यशाला स्टाफ के पेंशन व उपदान के मामले।
10. सेवा सम्बन्धी सभी मामले।
11. 10,000/-रु० से कम की प्रासंगिक व्यय स्वीकृति।
12. नयाचार कार्य।
13. वाहनों का बन्दोवस्त व लगाना।
14. बजट तैयार करना।
15. अधिकता व अभयर्पण विवरण।
16. वेतन यात्रा भता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल।
17. पेट्रोल व यात्रा भत्ते के अग्रिम की स्वीकृति।

18. सामान्य प्रशासन—क से सम्बन्धित अन्य सभी विविध मामले, उन मामलों के अतिरिक्त जो कि समय समय पर जारी किए गये नियमों/आदेशों/अनुदेशों के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों को न भेजे जाने हों।

4. अनुभाग अधिकारी के स्तर पर :

1. अनुस्मारक जारी करना।
2. विशिष्ट मामले से सम्बन्धित सूचना।
3. अन्य नैस्यिक व अनावश्यक मामले, जिन्हें अनुभाग अधिकारी के स्तर पर निपटाया जा सकता हो तथा अधिकारियों को भेजना आवश्यक न हो।
4. प्रारूप का अनुमोदन जहां कि अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किए जा चुके हों।
5. विभिन्न रिपोर्ट व रिटर्नज, अन्तरिक रिपोर्ट/उत्तर।
6. सम्बन्धित नस्ति/पूर्ण विवरण उपलब्ध न रहने पर पावतियों को लम्बित करना।
7. सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ स्टाफ को आकस्मिक/प्रतिपूरक/वैकल्पिक अवकाश की स्वीकृति देना।
8. उपस्थित पंजी का अनुरक्षण व जांच।
9. नैस्यिक/आम मामले का निपटारा।
10. उन दस्तावेजों का अधिप्रमाणन जिनमें वित्तिसय विवक्षा न उलझी हो।
11. विभागध्यक्षों से गाड़ियों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना।

ख—अनुभाग

1. मुख्य सचिव स्तर

1. विधि मामले

1. समादेश याचिकाएं।
2. निर्णयों के विरुद्ध।
3. सी.पी.सी की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस।
4. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि/भवन का अर्जन।

2. नीति तथा कार्यक्रम

1. विभाग के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट।
2. कार्य का पुनर्गठन तथा पुनर्वितरण।

3. स्थापना

1. राज्यपाल सचिवालय/प्रधान आवासीय आयुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली के कार्यालय में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन तथा संवर्ग का निर्धारण करना।
2. अस्थाई पदों का स्थाई पदों में परिवर्तित करना।
3. अस्थाई पदों की अवधि में विस्तार करना।(प्रासंगिक भुगतान पदों सहित)
4. नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, स्थायीकरण तथा पदच्युति के विरुद्ध द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की अपील याचिकायें।
5. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, दक्षता—रोध को रोकना, पेन्शन, वरिष्ठता तथा पुनर्नियोजना।

6. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का दक्षतारोध पार करना ।
7. द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सम्बन्ध में विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति का गठन करना व कार्यवाही करना ।
8. द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के बाद सेवा में रखना ।
9. वित्त विभाग की सहमति से विशेष वेतन की स्वीकृति ।
10. जहां वित्त की स्वीकृति अपेक्षित हो, सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति ।
11. द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, लघु दण्ड ।
12. नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थायीकरण तथा पदच्युति के विरुद्ध प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का अभिवेदन ।
13. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सर्तकता मामलें

4 बजट लेखा तथा वित्तीय मामले

1. स्थाई प्रभार सहित अन्तर्विष्ट मदों के आयव्ययक अनुमान ।
2. एकदम नई योजनाओं के लिए आयव्ययक अनुमान ।
3. नई योजनाओं का प्रयासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति ।
4. 1,00,000 रु० तक की प्रासंगिक स्वीकृति ।
5. हानियों तथा 10,000 रु० से 50,000 रु० के बीच की कीमत की अप्रयोज्य वस्तुओं हानियों को बटटे खाते में डालना ।
6. लेखा परीक्षा पैरा ।
7. एन.आर.सी.बिलों का भुगतान ।
8. आर.एण्ड जी. का भुगतान (वायरलैस स्टेशन)

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मामले जिन्हें मुख्य सचिव आवश्यक समझे भी प्रस्तुत किए जाएंगे ।

2. प्रधान सचिव/सचिव के स्तर पर

1. विधि मामले

1. समादेश याचिकाएं ।
2. निर्णयों के विरुद्ध ।
3. सी.पी.सी की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस ।
4. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि/भवन का अर्जन ।

2. नीति तथा कार्यक्रम

1. विभाग के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट ।
2. कार्य का पुनर्गठन तथा पुनर्वितरण ।

3. स्थापना

1. राज्यपाल सचिवालय/प्रधान आवासीय आयुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली के कार्यालय में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन तथा संवर्ग का निर्धारण करना ।

2. अस्थाई पदों का स्थाई पदों में परिवर्तित करना।
3. अस्थाई पदों की अवधि में विस्तार करना। (प्रासंगिक भुगतान पदों सहित)
4. आयोग के माध्यम से भर्ती करने हेतु मांग के आदेश देना।
5. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का सेवा में प्रयोजन।
6. नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, स्थायीकरण तथा पदच्युति के विरुद्ध द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की अपील याचिकायें।
7. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, दक्षता-रोध को रोकना, पेन्शन, वरिष्ठता तथा पुनर्नियोजन।
8. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का दक्षतारोध पार करना।
9. द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवा से/में प्रतिनियुक्ति।
10. राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सिविल तथा अपराधिक कार्यवाही के अनुदेश जारी करना तथा वापिस लेना और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किए गए या उनके विरुद्ध किए गए मुकदमों की राजकोष से क्षतिपूर्ति करना।
11. द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सम्बन्ध में विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति का गठन व कार्यवाही करना।
12. द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के बाद सेवा में रखना।
13. वित्त विभाग की सहमति से विशेष वेतन की स्वीकृति।
14. जहां वित्त की स्वीकृति अपेक्षित हो, सामान्य भविष्य निधि अंग्रिम की स्वीकृति।
15. द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, लघु दण्ड।
16. नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थायीकरण तथा पदच्युति के विरुद्ध प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का अभिवेदन।
17. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सर्तकता मामलें
18. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सन्दर्भ तथा उनके परामर्श से व्यवहृत मामले।

4. बजट लेखा तथा वित्तीय मामले :

1. स्थाई प्रभार सहित अन्तर्विष्ट मदों के आयव्ययक अनुमान।
2. एकदम नई योजनाओं के लिए आयव्ययक अनुमान।
3. नई योजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति।
4. 1,00,000 रु० तक की प्रासंगिक स्वीकृति।
5. हानियों तथा 10,000 रु० से 50,000 रु० के बीच की कीमत की अप्रयोज्य वस्तुओं हानियों को बट्टे खाते में डालना।
6. लेखा परीक्षा पैरा।

7. एन.आर.सी. बिलों का भुगतान।
8. आर.एण्ड जी. का भुगतान
9. वीरता पुरस्कार विजेताओं को नगदी ईनाम और अनुग्रह अनुदान।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मामले जिन्हें उपरोक्त अधिकारी आवश्यक समझे भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. अतिरिक्त/संयुक्त/उप/अवर सचिव के स्तर पर :

1. अन्तर्राज्यीय सीमा सम्बन्धित मामले।

राज्य के भीतर सम्बन्धित विभाग के साथ सभी नेमी प्रकृति का पत्राचार।

2. हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक की रेल सुविधायें।

रेलवे आरक्षण से सम्बन्धित मामले।

3. विधान सभा प्रश्न/आश्वासन।

सभी नेमी मामले तथा आंकड़े आदि इक्ठठा करना।

4. जिलों/उप मण्डलों/तहसीलों का पुर्नगठन।

नेमी प्रकृति का सभी पत्राचार जहां नीति निर्धारित की गई हो।

5. हिमाचल प्रदेश में डाकतार व बेतार सुविधाएं तथा सम्बन्धित मामले।
6. राज्यपाल सचिवालय/आवासीय आयुक्त कार्यालय—नेमी प्रकृति के सभी मामले।
7. जिला प्रशासन का पुर्नगठन—नेमी प्रकृति के सभी मामले।
8. शासक उनकी सम्पत्ति तथा राज भत्ते—नेमी प्रकृति के सभी मामले।
9. जनगणना से सम्बन्धित सभी मामलों।
10. सीमा विवाद—राज्यों के साथ पत्र व्यवहार।
11. पंजाब के पुर्नगठन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं जिनमें समेकन/आबंटन तथा परिसम्पत्तियों और उत्तरदायित्व भी शामिल हैं, से सम्बन्धित सभी नेमी पत्र व्यवहार।
12. शिकायत कक्ष/प्रतिवेदन सैल से सम्बन्धित नेमी पत्र व्यवहार।
13. भारत के राष्ट्रपति भवन, प्रधान मन्त्री सचिवालय, मुख्य मन्त्री/मन्त्री/राज्यमन्त्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आम जनता की विविध मांगों से सम्बन्धित पत्र व्यवहार।

4. अनुभाग अधिकारी के स्तर पर :

1. अनुस्मारक तथा पावती जारी करना।
2. विशिष्ट मामले से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना।
3. अन्य अनावश्यक मामले, जिन्हें अनुभाग अधिकारी के स्तर पर निपटाया जा सकता हो तथा अधिकारियों को भेजना आवश्यक न हो।
4. प्रारूप का अनुमोदन जहां कि अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किए जा चुके हों।
5. विभिन्न रिपोर्ट व रिटर्नज, आन्तरिम रिपोर्ट/उत्तर।
6. सम्बन्धित नस्ति/पूर्ण विवरण उपलब्ध न रहने पर पावतियों को लम्बित करना।
7. सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ स्टाफ को आकस्मिक/प्रतिपूरक/वैकल्पिक अवकाश की स्वीकृति देना।
8. उपस्थित पंजी का अनुरक्षण व जांच।
9. उन दस्तावेजों का अधिप्रमाणन जिनमें वित्तीय विवेक्षा न उलझी हो।

ग-अनुभाग**1. मुख्यसचिव के स्तर पर :**

1. मन्त्रीमण्डल/मन्त्रीमण्डलीय उप समिति की कार्य-सूची को तैयार करना।
2. राज्यपाल अभिभाषण का प्रारूप तैयार करना तथा उसका अनुमोदन करवाना।
3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (निरहर्ताएं) अयोग्यता निवारण नियम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा।
4. विधान सभा सत्र को बुलाने/सत्रावसान से सम्बन्धित मामले।
5. हिमाचल प्रदेश विधान सभा से सम्बन्धित प्रशासनिक/अन्य महत्वपूर्ण मामलों।
6. हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य संचालन नियम तथा आवंटन नियमों में संशोधन करना।
7. मंत्रियों/अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान सभा तथा विधायकों को दिए जाने वाले वेतन व भत्तों बारे अधिनियम बनाना तथा उन्हें दी जाने वाली सुख सुविधाओं से सम्बन्धित पत्राचार।
8. मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा से सम्बन्धित पत्राचार।
9. मुख्य सचेतक/सचेतक कॉन्फ्रेंस और इससे सम्बन्धित सभी मामलों।
10. राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण मामलों।
11. सामान्य प्रशासनिक विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।
12. राज्यस्तरीय कौमी एकता सप्ताह समारोह से सम्बन्धित पत्राचार।
13. संसदीय/विधान सभा प्रश्नों की स्वीकृति।
14. मन्त्रीमण्डल से सम्बन्धित सभी गोपनीय/गुप्त मामलों से सम्बन्धित पत्राचार।
15. मुख्यमन्त्री द्वारा सदन में सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित दिए गए आश्वासनों से सम्बन्धित पत्राचार।
16. हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन नियमावली के नियम-5 के अर्न्तगत विषय आवंटन का निर्णय।
17. मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा बताए गए अन्य महत्वपूर्ण मामलों।

2. प्रधान सचिव/सचिव के स्तर पर :

1. राज्यपाल अभिभाषण को तैयार करने के लिए सामग्री एकत्रित करना।
2. हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य संचालन तथा आवंटन नियमों की व्याख्या व स्पष्टीकरण सम्बन्धी।
3. राष्ट्रीय एकता समिति से सम्बन्धित सभी मामले।
4. प्रदेश में 19 नवम्बर से 25 नवम्बर तक मनाये जाने वाले "कौमी एकता सप्ताह" मनाने बारे।
5. मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गये आश्वासनों के कार्यान्वयन बारे पत्राचार।
6. मन्त्रीमण्डल के विचारार्थ ज्ञापन तैयार करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन/निर्देश जारी करना।
7. संसदीय/विधान सभा प्रश्नों/प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
8. विधान सभा सत्र को बुलाने व सत्रावसान करने सम्बन्धी मामले।
9. मंत्रियों/विधान सभा अध्यक्ष/राज्य मंत्रियों/उपाध्यक्ष/उप मंत्रियों/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिवों को दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित मामले।
10. मुख्य सचेतक/सचेतक कॉन्फ्रेंस से सम्बन्धित पत्राचार।
11. अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपीलें।

3. विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/अवर सचिव के स्तर पर :

1. राज्यपाल अभिभाषण को तैयार करने के लिए आंकड़े/सामग्री एकत्रित करना।
2. हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य संचालन नियम तथा आवंटन नियम की व्याख्या व स्पष्टीकरण सम्बन्धित पत्राचार।
3. राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सभी मामले।
4. विधान सभा प्रश्नों तथा प्रस्तावों से सम्बन्धित सभी मामले।
5. मन्त्रीमण्डल द्वारा लिए गये निर्णयों को प्रेषित करना।

6. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (निरहर्ताएं) अयोग्यता निवारण नियम से सम्बन्धित सभी मामले।
7. मुख्य सचेतक/सचेतक कॉन्फ्रेंस से सम्बन्धित सभी मामले।
8. विधायकों/सांसदों के समितियों में मनोनयन बारे अध्यक्ष लोक सभा/सभापति राज्यसभा/अध्यक्ष विधान सभा से पत्राचार।
9. विधान सभा से सम्बन्धित प्रशासनिक/बजट और लेखा आदि मामलों बारे पत्राचार।

अनुभाग अधिकारी के स्तर पर :

1. अनुस्मारक जारी करना।
2. विशिष्ट मामले से सम्बन्धित सूचना।
3. अन्य अनावश्यक मामले, जिन्हें अनुभाग अधिकारी के स्तर पर निपटाया जा सकता हो तथा अधिकारियों को भेजना आवश्यक न हो।
4. प्रारूप का अनुमोदन जहां कि अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किए जा चुके हों।
5. विभिन्न रिपोर्ट व रिटर्नज, आन्तरिम रिपोर्ट/उत्तर।
6. सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ स्टाफ को आकस्मिक/प्रतिपूरक/वैकल्पिक अवकाश की स्वीकृति देना।
7. उपस्थित पंजी का अनुरक्षण व जांच।
8. उन दस्तावेजों का अधिप्रमाणन जिनमें वित्तिय विवक्षा न उलझी हो।

डी-अनुभाग

1. मुख्यसचिव के स्तर पर :

1. सरकारी आवासों का आबंटन तथा कार्यालय भवनों के आवासीय भवनों में बदलने तथा परस्पर परिवर्तन के मामले।
2. आवास आबंटन समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।
3. श्रेणी 4 तथा इससे उपर के आवासों से परिवर्तन सम्बन्धी मामले।
4. अन्य मामले जिन्हें सचिव महोदय मुख्य सचिव से अनुमोदित करवाना चाहें।
5. अन्य सभी मामले जिन्हें वे देखना चाहें।

2. प्रधान सचिव/सचिव के स्तर पर :

1. सम्पदा निदेशालय हिमाचल प्रदेश में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने सम्बन्धी मामले।
2. सम्पदा निदेशालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थापना से सम्बन्धित मामले।
3. सम्पदा निदेशालय हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के आवास ऋण व प्लॉट इत्यादि खरीदने से सम्बन्धित मामले।
4. पारगमन आवास के आबंटन सम्बन्धी मामले।
5. दस हजार से अधिक तथा 2.50 लाख तक खर्च करने की अनुमति।
6. ऑडिट पैरा जो कि ऑडिटर जनरल एवं कम्पट्रोलर द्वारा भेजे गये हों।
7. आधिक्य एवं अभ्यापरण सूचियां।
8. I से III वर्ग तक आवासों के परिवर्तन सम्बन्धी मामले।
9. गैराजों/सेवक आवासों का आबंटन एवं परिवर्तन।
10. वार्षिक कार्य योजना।
11. अनौपलब्धि आवास प्रमाण पत्र (प्रथम बार)।
12. सचिवों की बैठक/संयुक्त सलाहकार समिति/जन-जातीय सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेना।
13. आवासों के निर्माण, नवीनीकरण एवं नये आवास खरीदने बारे मामले।

14. हिमाचल प्रदेश नई दिल्ली/चण्डीगढ़ की दरों का निर्धारण जो कि मुख्य सचिव महोदय की स्वीकृति से निर्धारित किए जाएंगे।
15. आवासों के वर्ग को बदलने सम्बन्धी मामले।
16. अन्य सभी मामले जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं का निपटारा।
17. अन्य सभी मामले जो वे देखना चाहें।

3. विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/अवर सचिव के स्तर पर:

1. हिमाचल भवन नई दिल्ली, चण्डीगढ़ व लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह शिमला के आरक्षण सम्बन्धी मामले।
2. अन्य सभी मामले जिन्हें सचिव महोदय को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
3. दस हजार से कम तक के मामले।
4. आवासों की मुरम्मत सम्बन्धी मामले।
5. सम्पदा निदेशालय हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के भविष्य निधि अग्रिम सम्बन्धी मामले।
6. वे सभी मामले जिन्हें वे देखना चाहें।

अनुभाग अधिकारी के स्तर पर :

1. अनुस्मारक जारी करना।
2. विशिष्ट मामले से सम्बन्धित सूचना।
3. अन्य अनावश्यक मामले, जिन्हें अनुभाग अधिकारी के स्तर पर निपटाया जा सकता हो तथा अधिकारियों को भेजना आवश्यक न हो।
4. प्रारूप का अनुमोदन जहां कि अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किए जा चुके हों।
5. विभिन्न रिपोर्ट व रिटर्नज, आन्तरिम रिपोर्ट/उत्तर।
6. सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ स्टाफ को आकस्मिक/प्रतिपूरक/वैकल्पिक अवकाश की स्वीकृति देना।
7. उपस्थित पंजी का अनुरक्षण व जांच।
8. उन दस्तावेजों का अधिप्रमाणन जिनमें वित्तिय विवक्षा न उलझी हो।

ई—अनुभाग

1. मुख्यसचिव के स्तर पर :

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के सदस्य सचिव होने के नाते ऐसे सभी मामले जो कि बोर्ड में रखे जाते हैं उनका निपटारा करने हेतु निर्णय लेते हैं तथा मुख्य मंत्री महोदय को स्वीकृति हेतु भेजते हैं।
2. अन्य सभी मामले जो स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित होते हैं तथा बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सभी मसौदे अपने सुझाव सहित मुख्य मंत्री महोदय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

2. प्रधान सचिव/सचिव के स्तर पर :

1. स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण कार्य के नीतिगत मामले का निपटारा करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
2. स्वतंत्रता सेनानी सम्मान राशि हेतु सभी मामले जिन की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त होती है, उनको अनुमोदित करना।
3. स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड तथा उप समिति का मदों पर पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान करना।
4. न्यायालयों में स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में सरकार की ओर से उत्तर देने हेतु निर्णय लेना।

5. अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण हेतु मामले जो अतिरिक्त/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव द्वारा स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं।
6. बजट में प्रावधान तथा अनुपूरक मांग जो सरकार से कल्याण हेतु मांगी जाती है, उनकी स्वीकृति प्रदान करना।
7. कल्याण बोर्ड तथा इसकी उप समिति की बैठकों के मदों पर मसौदों को पूर्णतः टिप्पणी करके मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री महोदय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
8. मंत्रीमण्डल की स्वीकृति हेतु यदि कोई मामला हो तो उसका निपटारा करना।

3. विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/अवर सचिव के स्तर पर :

1. अनुभाग में सभी कार्य के बारे में पत्राचार तथा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा पूछी गई सूचनाओं को भेजने हेतु सभी पत्राचार/पत्रों को जारी करना।
2. भारत सरकार से स्वतंत्रता सेनानी मामले में जो भी सूचना मांगी जाये उन पत्रों को जारी करना।
3. स्वतंत्रता सेनानी/उनकी पत्नी/विधवाओं के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करना।
4. बतौर कोषपाल, चैरीटेबल इन्डोमेंट फण्ड के सभी चैकों पर हस्ताक्षर करना तथा रोकड़ बही में हस्ताक्षर करना।
5. स्वतंत्रता सेनानी उप समिति के सदस्य सचिव होने के नाते बैठकों की कार्यवाही लिखने का कार्य।
6. स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड की उप समिति की बैठकें बुलाने हेतु कार्य करना।
7. अन्य सभी कार्य जो अनुभाग अधिकारी के अधीन नहीं आते उन सभी कार्यों/नस्त्रियों का निपटारा करना।
8. वे सभी मामले जो कि बोर्ड तथा उप समिति की बैठक में पारित होते हैं उन को कार्यान्वित करने हेतु सभी विभागों से पत्राचार करना।
9. स्वतंत्रता सेनानियों के न्यायिक मामलों पर न्यायालय में उत्तर दायर करना।

4. अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन के स्तर पर :

1. सूचनार्थ पत्रों को नस्ति करना तथा प्रथम व द्वितीय अनुस्मारक जारी करना।
2. स्वतंत्रता सेनानी सम्मान राशि/अनुदान राशि के चैक/ड्राफ्ट के उपर अग्रपत्र भेजना।
3. स्वतंत्रता सेनानियों को भुगतान की सरकारी रोकड़ बही को चैक करना।
4. स्वतंत्रता सेनानियों को भुगतान की कोषपाल चैरीटेबल इन्डोमेंट फण्ड की रोकड़ बही को चैक करना।
5. स्वतंत्रता सेनानी न्यायालय सम्बन्धी मामलों पर न्यायालय में बुलाने पर विभाग की ओर उपस्थित होना तथा अभिलेख प्रस्तुत करना।
6. स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं के पहचान पत्रों पर के उपर अग्रपत्र भेजना।
7. दूसरे विभागों द्वारा सूचनार्थ मांगी सूचना के सम्बन्ध में पत्र जारी करना इत्यादि।

ANNEXURE-III

Directory of its officers and employees

Sr.No.	Name & Designation	Telephone Nos.(office)	Address(office)
1.	Smt. Asha Swarup, Chief Secretary	2621022	HP. Secretariat
2.	Dr.Ajai Bhandari, Secretary (GAD)	2621892	H.P. Secretariat

3.	Sh. J.R. Katwal, Special Secretary(GAD)	2621007	H.P. Secretariat
4.	Smt. Sumati Negi, Deputy Secretary (GAD)	2621110	H.P. Secretariat.
5.	Sh. Harish Chander Negi, Section Officer, GAD-A	2880423, 2880523	H.P. Secretariat
6.	Smt.Savitri Joshi, Section Officer, GAD-B	2880424	H.P. Secretariat
7.	Sh.Ramesh Verma, Section Officer, GAD-C	2880425, 2880525	H.P. Secretariat
8.	Sh.M.C.Kaundal,Section Officer, GAD-D	2880426, 2880830,	H.P. Secretariat
9.	Sh. Rajinder Thakur, Section Officer, GAD-E	2880428	H.P. Secretariat

ANNEXURE-IV

The Monthly Remuneration Received by each of its Officers and Employees, including the System of Compensation as Provided in Regulations.

The salaries and allowances of the employees of the General Administration Department are those as prescribed by the Finance Department from time to time for Himachal Pradesh Government employees of different categories. The detail are as follows:

Sr.No.	Post	Pay Scale
1.	Secretary	Rs.37400-67000(plusgrade pay)
2.	Special Secretary	Rs.14300-18600
3.	Deputy Secretary	Rs 12000-15500
4.	Section Officer	Rs.7220-11660
5.	Superintendent	Rs.6400-10640
6.	Superindent	(Ex-Cadre) Rs.6400-10640
7.	Senior Assistant	Rs.5800-9200
8.	Junior Assistant	Rs.4400-7200
9.	Clerk	Rs.3220-5160
10.	Peon	Rs.2620-4250
11.	Supervisor	Rs.4020-6200
12.	Driver	Rs.4020-6200
13.	Head Mechanic	Rs.4400-7000
14.	Mechanic	Rs.4020-6200
15.	Fitter	Rs.3120-5160